भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन व्यापार समझौता

भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन (ईएफटीए) ने 10 मार्च, 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) पर हस्ताक्षर किए। यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन (ईएफटीए) चार देशों आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का समूह है। वार्ता अक्टूबर, 2008 में शुरू हुई और दिसंबर, 2019 में निष्क्रियता के चरण में चली गई। अगस्त 2023 में 19वें दौर की वार्ता के साथ इसे पुनर्जीवित किया गया और अगले आठ महीनों की अवधि में इसका समापन हुआ। हालाँकि, इसे लागू करने के लिए अब दोनों पक्षों को इसका अनुमोदन करना होगा।

हस्ताक्षर समारोह में, भारत के माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा उठाए गए मुख्य विषय फार्मास्यूटिकल्स, अनुसंधान और विकास, प्रसंस्कृत खाद्य, हरित ऊर्जा मशीनरी आदि,जैसे कई क्षेत्रों के लिए समझौते द्वारा प्रदान किए गए अपार अवसरों के बारे में थे। माननीय स्विस मंत्री श्री गाइ पार्मेलिन ने विविधता और मतभेदों का सम्मान करने की आवश्यकता के बारे में बात की। उन्होंने संकेत दिया कि दोनों अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे की पूरक हैं और समग्र परिणाम न्यायसंगत हैं। आइसलैंड के माननीय मंत्री श्री बजरनी बेनेडिक्टसन ने कहा कि टीईपीए दोनों देशों के बीच संबंधों को

मजबूत करेगा। लिकटेंस्टीन की माननीय मंत्री सुश्री डोमिनिक हस्लर ने अपने देश में नवीन कंपनियों की उपस्थिति के बारे में बात की जो भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग कर सकती हैं। अंत में, नॉर्वे के माननीय मंत्री श्री जान क्रिश्चियन वेस्ट्रे ने संकेत दिया कि यह समझौता निवेश और सेवाओं की पूर्वानुमेयता सुनिश्चित करेगा। यह बताते हुए कि नॉर्वे द्वारा निवेश का मौजूदा स्तर 25 अरब डॉलर है, समझौते के परिणामस्वरूप इसमें वृद्धि होगी। उन्होंने यह भी बताया कि निवेश करने की इच्छुक कंपनियों की सहायता के लिए भारत में एक यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन (ईएफटीए) कार्यालय खोला जाएगा।

यह समझौता वास्तव में यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन (ईएफटीए) और भारत के बीच आर्थिक संबंधों के लिए एक सीमाचिह्न है। यह पश्चिमी गोलार्ध में विकसित देशों के साथ पहला व्यापार समझौता होगा और अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ाव का द्वार खोलेगा। जबकि भारत कृषि उत्पादों और वस्त्रों के निर्यात के अवसरों का लाभ उठा सकता है, कई कंपनियां यूरोपीय संघ जैसे आसपास के बड़े बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए सहयोग कर सकती हैं। यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन (ईएफटीए) देशों के लिए, भारत में निवेश करने और बाजार पहुंच हासिल करने का अवसर है। कुछ संभावित क्षेत्र जहां दोनों साझेदार लाभान्वित होंगे, वे बुनियादी ढांचा, लॉजिस्टिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स हैं। रसायन, मशीनरी, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ, बीमा आदि इसके अलावा, यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन (ईएफटीए) ने अगले 15 वर्षों में लगभग 100 बिलियन डॉलर का एफडीआई प्रतिबद्ध किया है। इसके अलावा, यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन (ईएफटीए) ने अगले 15 वर्षों में लगभग 100 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

लाने का वादा किया है। प्रस्तावित निवेश और बढ़े हुए व्यापार से लगभग 10 लाख अतिरिक्त नौकरियाँ पैदा होंगी। यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा भी प्रदान करेगा और देश में तकनीकी उन्नयन के लिए सुविधाएं भी तैयार करेगा।

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र इन वार्ताओं में उत्पत्ति के नियम ट्रैक पर शामिल होने से खुश थी। पदों में मूलभूत अंतर को देखते हुए बातचीत कठिन थी। हालाँकि, दोनों पक्ष एक समझौते पर मुहर लगाने के लिए अपनी मौजूदा स्थिति से आगे बढ़ गए, जो यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी टैरिफ रियायत का लाभ उठाने के लिए दोनों अर्थव्यवस्थाओं में पर्याप्त प्रसंस्करण हो।

उत्पाद विशिष्ट नियमों (पीएसआर) के संबंध में, यह अधिकांश कच्चे कृषि उत्पादों के लिए पूर्ण रूप से प्राप्त किया जाता है। प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के लिए, यह या तो टैरिफ वर्गीकरण में बदलाव (सीटीसी) और मूल्यवर्धन या केवल सीटीसी का मिश्रण है। औद्योगिक वस्तुओं के लिए, यह काफी हद तक सीटीसी और मूल्यवर्धन, सह-समान नियमों के साथ-साथ सीटीसी का मिश्रण है। नियमों का उद्देश्य पर्याप्त प्रसंस्करण मानदंड और व्यापार सुविधा के बीच एक अच्छा संतुलन सुनिश्चित करना है।

इस व्यापार समझौते के मूल ट्रैक के नियमों में कुछ प्रमुख अवधारणाएँ 10% की न्यूनतम सीमा हैं; अपर्याप्त कामकाज या प्रसंस्करण जो स्वयं मूल स्थिति प्रदान नहीं करेगा; पारगमन की व्यवस्था लेकिन उचित दस्तावेज़ीकरण के साथ; उपयोग किए गए

इनपुट आदि के लिए उत्पत्ति प्रदान करने के लिए रोल-अप या अवशोषण।

प्रमाणीकरण पर, भारत ने अपने निर्यातकों के लिए स्व-प्रमाणन की अवधारणा पेश की थी। इससे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम हो जाएगा। हालाँकि, ऐसे मामलों में जहां वे नियमों के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं, अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से प्रमाणन का विकल्प भी मौजूद है। इन दोनों मूल प्रमाण पत्र का एक विशिष्ट प्रारूप है जिसे निर्यातकों को भरना और हस्ताक्षर करना होता है। यह सब डीजीएफटी के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना होगा जिसमें निर्यातकों को पंजीकृत होना होगा।

समझौते के लिए सत्यापन प्रक्रियाएँ मजबूत हैं। उत्पत्ति के सभी प्रमाणों के लिए एक प्रमाणीकरण तंत्र है। इसके अलावा, प्रक्रिया के लिए समय-सीमाएं हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि सत्यापन शीघ्रता से किया जाए। इसके अलावा, आयात करने वाले देशों के सीमा शुल्क प्राधिकरण को उल्लंघन के मामले में टैरिफ रियायतों को निलंबित करने का अधिकार है। बार-बार उल्लंघन की स्थिति में विशिष्ट निर्यातकों और यहां तक कि उत्पादों के लिए रियायतों का अस्थायी निलंबन संभव है।

समझौते के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र और निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) सहित भारतीय निर्यातकों को कुछ प्रमुख पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है:

I. निर्यात किए जा रहे उत्पाद की उत्पत्ति के नियम जानें

II. सुनिश्चित करें कि उत्पादन प्रक्रिया की मूल्य श्रृंखला के बारे में पर्याप्त जानकारी हो।
III. स्व-प्रमाणित केवल तभी करें जब आपके पास सभी दस्तावेज़ हों और निर्यात किए जा रहे उत्पाद की उत्पत्ति के नियमों के बारे में निश्चित हों।
IV. यह न मानें कि यदि कोई उत्पाद घरेलू बाजार से प्राप्त किया गया है, तो वह भारतीय मूल का है। पूरी तरह से प्राप्त मानदंडों का उपयोग केवल तभी करें जब कोई पूरी तरह से आश्वस्त हो कि पूरी उत्पादन प्रक्रिया भारत में हुई है। इस संदर्भ में, पूरी तरह से प्राप्त मतलब क्या है, इसके नियमों को पढ़ना महत्वपूर्ण है।
V. डीजीएफटी के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खुद को रजिस्टर करें
VI. उत्पाद की उत्पत्ति के नियमों की पुष्टि के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र का कार्यालय निर्यातकों की किसी भी मदद के लिए तैयार रहेगा। कृपया बेझिझक dc@nsez.gov.in; jdc@nsez.gov.in; ddc1@nsez.gov.in या ddc3@nsez.gov.in पर संपर्क करें;

****